एनएमआरसी ने पत्र लिखकर 24 मई को दोपहर 12 बजे बैठक में बुलाया है, कमाई के लिए को-ब्रांडिंग करने का निर्णय

नोएडा-ग्रेनो मेट्रो स्टेशन सरकारी संस्थानों के नाम पर होंगे

तैयारी

नोएडा | वरिष्ठ संवाददाता

नोएडा-ग्रेनो मेट्रो लाइन के स्टेशनों को अपने नाम के साथ जुड़वाने के लिए सरकारी एजेंसियों को एनएमआरसी ने आमंत्रित किया है। इसके लिए 33 सरकारी संस्थानों को पत्र लिखकर 24 मई को दोपहर 12 बजे बैठक में बुलाया है।

इस लाइन पर 21 मेट्रो स्टेशन हैं। कमाई के लिए एनएमआरसी ने सभी स्टेशनों की कों-ब्राडिंग करने का निर्णय ले रखा है। इसके तहत कंपनियों के नाम स्टेशन के नाम के साथ जोड़े जाएंगे। इसके बदले उन्हें उस स्टेशन की मरम्मत का का 10 साल तक करना होगा। संबंधित कंपनी को बदले स्टेशन पर विज्ञापन का अधिकार दिया जाएगा।

एनएमआरसी की प्रवक्ता संध्या शर्मा ने बताया कि 21 में से 5 स्टेशन ओपन टेंडर के जरिए कंपनियों को दिए जा चुके हैं। इनमें सेक्टर-137, 142, नॉलेज पार्क दो, परी चौक और अल्फा वन स्टेशन शामिल हैं।

अब नोएडा क्षेत्र के 11 स्टेशनों को सरकारी एजेंसियों को देने का निर्णय लिया गया है। इनमें सेक्टर-76, 101, 81, एनएसईजेड, 83, 143, 144, 145, 146, 147 और डिपो स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों को देने के लिए एनटीपीसी, ओएनजीसी, बीएचईएल, एनबीसीसी, एमटीएनएल, यूनियन बैंक, केनरा बैंक, आईडीबाई सहित अन्य सरकारी एजेंसी हैं। प्रवक्ता ने बताया कि अभी सरकारी संस्थान थर्ड पार्टी के जरिए स्टेशन लेते हैं। इसमें उनका अधिक खर्चा होता है। ऐसे में इन सरकारी संस्थानों को सीधे बुलावा भेजा गया है। इसमें उनका कम खर्चा आएगा।

गौरतलब है कि नोएडा-दिल्ली के बीच चल रही ब्लू लाइन के भी कई स्टेशनों को कंपनियां ले चुकी हैं। इनमें वेब ग्रुप ने सेक्टर-32 सिटी सेंटर और सेक्टर-18 को ले रखा है। बाकी स्टेशन भी अलग-अलग कंपनियों ने ले रखे हैं।

कमाई के लिए अन्य योजनाओं पर भी काम : एनएमआरसी आय बढ़ाने के लिए अन्य योजनाओं पर भी काम कर रहा है। इनमें फिल्म शूटिंग, स्टेशनों पर दुकान-बेक्वेंट हॉल के अलावा अन्य योजनाओं पर काम कर रहा है।

वॉक वे काम में तेजी लाने के निर्देश

एनएमआरसी के कार्यकारी निदेशक पीडी उपाध्याय ने सोमवार शाम सेक्टर-51 स्टेशन का दौरा किया। यहां पर सेक्टर-51 व 52 स्टेशन के बीच वॉक वे बनाया जा रहा है। यहां पर बारिश के बाद पानी भर गया था। आगे से बारिश में पानी न भरे इसके लिए इसे ऊंचा उठाकर बनाने का निर्णय लिया गया है।